

विकसित भारत समाचार

वर्ष : 09 | अंक : 176 |

गुवाहाटी | बुधवार, 18 जनवरी, 2023 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 12 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

बाक्सा में नाव पलटी, आठ को बचाया व
एक लापता

पेज 3

भारतीय सेना में पहली बार 108 महिला
अफसर बनेंगी कर्नल, आर्मी बोर्ड गठित

पेज 4

स्वास्थ्य विभाग में दवाओं के नाम पर मची है
लूट : अखिलेश

पेज 5

राजस्थान में कांग्रेस फिर
बनाएंगी सरकार : पायलट

पेज 8

पूर्वाञ्चल क्रेसी
(असमीया दैनिक)
PURVANCHAL KESARI
(ASSAMESE DAILY)
GOOD LUCK PUBLICATIONS
House No. 30, D. Neog Path,
ABC, Guwahati - 781005
Mob: 94350 14771, 97070 14771

मुस्लिम समाज के बारे में गलत

बयानबाजी ना करें : पीएम मोदी

भाजपा नेताओं को पीएम मोदी की नसीहत



चलेगा, सभी को संवेदनशील होने की जरूरत है। सत्ता में बैठे लोग ये ना समझें कि स्थानीय पीएम ने कार्यकारीओं के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। पीएम ने बीजेपी नेताओं को नसीहत दी और कहा कि मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और बोर्डर के बैठक के बारे में संगठन को मजबूत करने और कार्यकारीओं को बृथ को मजबूत करने के लिए निर्देश दिए। अलग-अलग जाहां पर

यूएन ने अब्दुल रहमान मव्की को ग्लोबल आतंकी घोषित किया



न्यूयॉर्क। लंबे समय से पाकिस्तानी आतंकवाली अब्दुल रहमान मव्की का समर्थन करते आ रहे चीन ने आधिकारिक अपाना हाथ खींच लिया है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी मव्की को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी की लिस्ट में डाल दिया है।

इससे पहले जब भी इसको लेकर प्रस्ताव पेश किया जाता था, चीन अड़ा लगा देता था। पूरी तरह उसके सामाजिक विभाग का बड़ा उत्तराधिकारी ने बोला कि मव्की को अंतर्राष्ट्रीय पहले ही आतंकी घोषित किया जाए। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी उसे ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में संशिलित कर दिया। बता दें कि बीते साल जून में भारत ने इसी बात को लेकर चीन को खबर प्रस्ताव लाया था तब चीन ने अंतर्राष्ट्रीय कारोंगों से इसपर असहमति जता दी थी। 75 साल के मव्की का लश्कर में बड़ा पद था और भारत ने भी अपने -शेष पृष्ठ दो पर

संपादकीय नए रोजगार की ओर

निर्णायक होने के कई मजमून हिमाचल का पीछा कर रहे हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द तमाम मुख्यमंत्रियों का आकलन होता रहा है। इसी फेहरिस्त में आने वाले पांच साल मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के हर फैसले का मूल्यांकन करेंगे। हिमाचल सरकार के तौर तरीके और पहली मंत्रिमंडलीय बैठक ने यह स्थापित कर दिया कि बात पैसे की भी हो, तो जिरह और जमीन बदली जा सकती है। औपरीएस मुद्रे पर वचनबद्धता निभाना बेशक चुनावी वादा था, लेकिन इस के ऊपर सरकार का रवैया और वित्तीय प्रबंधन का तरीका निश्चित तौर पर निर्णायक भूमिका में परिचय दे गया और अगर मुख्यमंत्री इस मामले से जुड़ी तमाम आपित्यों और शंकाओं से लोग गए, तो वह अपने क्रत्यावृण्डों, दृष्टिकोण और कार्रवाइयों में उत्सुकता का आभास कराते रहेंगे। अब तक मंत्रियों का चयन, विभागों का वितरण और मंत्रिमंडल के फैसलों का आगाज सुखविंदर सिंह को अलग श्रृंखला बनाते हुए देख रहा है। जाहिर है कि गांगेस की गांगटियां सरकार के गले से बंधी हुई हैं और ये खर्चीली तथा वित्तीय प्रबंधन की अति कठोर तपस्या से जुड़ी हुई हैं। दूसरी ओर राज्य की अपेक्षाएं, हिमाचल की प्राथमिकताएं और व्यवस्था परिवर्तन की धाराएं जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री को कड़क और निर्णायक फैसले लेते हुए देखना चाहती हैं। सरकार के अगले कदमों में तीन सौ यूनिट तक मुफ्त बिजली की आपूर्ति, एक लाख रोजगार के अवसर पैदा करने और अपने पहले बजट के अनुमानों में आत्मनिर्भरता, आशा, विकास और वित्तीय कुशलता भरने का संकल्प देखा जाएगा। यह दीगर है कि सरकार हर फैसले के पैरामीटर में समय सीमा

सरकार के अगले कदमों में तीन सौ यूनिट तक मुफ्त बिजली की आपूर्ति, एक लाख रोजगार के अवसर पैदा करने और 30प्रति पहले बजट के अनुमानों में आत्मनिर्भरता, आशा, विकास और वित्तीय कुशलता भरने का संकल्प देखा जाएगा। यह दीगर है कि सरकार हर फैसले के पैरामीटर में समय सीमा निर्धारित कर रही है और इसीलिए अगले एक महीने में महिला पेशन व रोजगार पर फैसला लेने वाली है। ऐसे में हिमाचल और युवाओं के भविष्य की दृष्टि से रोजगार सूजन पर आने वाली रिपोर्ट तथा इससे संबंधित फैसले का इंतजार स्वाभाविक है। यह इसलिए भी कि अब तक रोजगार के मायने सरकारी नौकरी रहे हैं और कमोबेश हर सरकार ने युवाओं को किसी न किसी बहाने इसी दिशा की ओर प्रेरित किया। इतना ही नहीं प्रदेश का अब तक का शैक्षणिक माहौल भी एक तरह से सरकारी नौकरी को ही इसका अभिप्राय बनाता रहा है। ऐसे में रोजगार की रफ्तार को समझाने के लिए युवा महत्वाकांक्षा और स्वरोजगार की संभावना को फिर से लिखने की जरूरत है। हिमाचल में एक लाख से कहीं अधिक रोजगार व्यापार, उद्योग, पर्यटन, परिवहन, स्वरोजगार, लोककलाओं, ग्रामीण व शहरी आर्थिकी से आ सकता है, बशर्ते ढांचागत परिवर्तन व नवाचार में सरकार आगे बढ़े। इस दिशा में युवाओं के लिए पूर्व घोषित स्टार्टअप फंड से काफी आशा रहेगी। पर्यटन को ही लें, तो सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में कम से

कम एक पर्यटन गांव विकसित करते हुए कहां हाम स्टे, गिफ्ट सेटर, जल पान गृह, मनोरंजन तथा अन्य गतिविधियों पर केंद्रित स्वरोजगार पैदा कर सकती है। ये पर्यटन गांव बिना किसी अतिरिक्त बजट के विधायक निधि, पर्यटन योजनाओं, ग्रामीण व शहरी विकास, जलशक्ति, पीडल्यूडी, बन, भाषा-संस्कृति, मत्स्य पालन तथा प्रमुख धार्मिक स्थलों की आय व सहयोग से विकसित हो सकते हैं। ये हाई-वे, धार्मिक इंको, साहसिक खेलों, हाट बाजार तथा मनोरंजन गतिविधियों को आगे बढ़ाता हुआ ऐसा ढांचा होगा, जहां पूरे प्रदेश में कम से कम पचीस हजार लोगों को रोजगार के अवसर दिए जा सकेंगे। इसी तरह पीडल्यूडी, ग्रामीण विकास व परिवहन विभाग अगर हर कर्से में बस स्टॉप कम व्यापारिक केंद्र विकसित करें तो कम से कम पचीस हजार नए व्यापारिक केंद्र स्थापित हो सकते हैं। प्रदेश में शहरीकरण से उपजे रोजगार का मूल्यांकन हो, तो ऐसी अधोसंरचना निर्मित हो सकती है, जो कम से कम 25000 युवाओं को पहले ही चरण में भविष्य का रास्ता दिखाएगी।

କୁଣ୍ଡ ଅଲଗ

सुप्राम काट क कालाजयम म अपना प्रतिनिधि क्यों चाहती है केंद्र सरकार?

कंद्रोय कानून मत्रा ने मुख्य न्यायाधीश का पत्र लिख कर मार्ग का है कि उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन करने वाले कॉलेजियम में सरकार का भी प्रतिनिधि होना चाहिए। इस पत्र पर हालांकि कॉलेजियम में चर्चों के बाद ही कोई निर्णय लिया जायेगा, लेकिन इस पर देश में बहस भी शुरू हो गयी है। कुछ न्यायविद् इसे एनजेएसी अधिनियम की वापसी बता रहे हैं तो वहीं सरकार से जुड़े लोगों का कहना है कि हमने कोई अभूतपूर्व मांग नहीं की है क्योंकि पूरी दुनिया में ही ऐसा होता है। कानून मंत्री का मानना है कि कॉलेजियम प्रणाली में सरकार का प्रतिनिधि होने से इसमें

पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही भी आएगी। देखा जाये तो उच्चतम न्यायालय की मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री के बयान के बाद कुछ पूर्व न्यायाधीशों ने भी इस मुद्दे पर बयान दिये जिस पर न्यायालय ने नाखुशी भी जताई थी। लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जिस तरह एनजेएसी अधिनियम को रद्द किये जाने पर संसद में चर्चा नहीं होने पर हैरत जताई थी, उससे अंदेशा हो गया था कि सरकार कोई कदम उठा सकती है। अब केंद्रीय कानून मंत्री ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कॉलेजियम में सरकार का प्रतिनिधि रखने की जो मांग की है उससे स्पष्ट हो गया है कि सरकार न्यायाधीशों के चयन के मुद्दे को सिफ्ट कॉलेजियम के भरोसे छोड़ने को तैयार नहीं है। उल्लेखनीय

की जो मांग की है उससे स्पष्ट हो गया है कि सरकार न्यायाधीशों के चयन के मुद्दे को सिर्फ कॉलेजियम के भरोसे छोड़ने को तैयार नहीं है। उल्लेखनीय है कि 2015-16 में संसद से पारित एनजेएसी में कॉलेजियम प्रणाली को पलटने का प्रावधान था, हालांकि शीर्ष अदालत ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। न्यायपालिका और सरकार के बीच कॉलेजियम प्रणाली पर मतभेद उस समय भी सामने आये थे जब हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केशवानंद भारती मामले में अदालत के ऐतिहासिक फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उपराष्ट्रपति अंतर्गत वीर संघर्षमय से

अदालत न इस अवधानक बताते हुए रद्द कर दिया था।

न्यायपालिका, संसद का संप्रभुता समझौता नहीं कर सकती। उल्लेखनीय है कि उस फैसले ने देश को 'संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत' दिया था। धनखड़ ने जयपुर में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को निरस्त किये जाने पर एक बार फिर सवाल उठाते हुए कहा था कि लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए संसदीय संप्रभुता और स्वायतता सर्वोपरि है। बहरहाल, न्यायपालिका और सरकार के बीच जो मतभेद दिख रहे हैं उसका हल सौहार्दपूर्ण तरीके से ही निकाला जाना चाहिए।

समय रहते वर्तमान पीढ़ी की सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा, अन्यथा भविष्य की पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी

सवाल सिर्फ जोशीमठ का नहीं

आदि

आदि शंकराचार्य द्वारा आठवीं शताब्दी में स्थापित है। शहर जिसमें पवित्र ज्योतिलिंगम स्थित है। जेसे जोशीमठ के नाम से जाना जाता है, के धंसने की खबर से उत्तराखण्ड ही नहीं, संपूर्ण देश में चिंता व्याप्त है। जहां एक ओर जोशीमठ शहर के धंसने से बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो रहे हैं और उनकी राजनीतिक दल एक-दूसरे पर दोषारोपण में व्यस्त हैं। 'जोशीमठ' वचाओं संर्धसमिति' के आंदोलन के चलते नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) को आदेश दिया गया है कि तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट के निर्माण, जिसमें हेलांग बायापास एवं सड़क भी शामिल है, को रोक दिया जाए। ऐश्वर्या की सबसे बड़ी रोपवेज के काम को भी रोक दिया गया है। इस संकट के मद्दनजनक बाह्य ये कदम उठाये गये हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि जोशीमठ के धंसने को रोका नहीं जा सकेगा। यानि आविष्कार शंकराचार्य द्वारा स्थापित इस पहले ज्योतिर्मठ के पतन को अब रोका नहीं जा सकता। यह पहला अवसर नहीं है कि इस हिमालय के क्षेत्र में इस प्रकार की त्रासदी हुई है। इससे पहले वर्ष 2021 में भी तपोवन बांध के मजदूरों सहित 200 लोगों की मौत चमोली बाद में हुई थी। इससे पूर्व 2013 में भी भारी वर्षा के बाद इस क्षेत्र में गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में पुल, सड़कें और भवन धराशायी हो गये थे। हिमालयी क्षेत्र में आये दिन इस प्रकार की आपदाओं में हाल ही के वर्षों में भारी बृद्धि हुई है। इन प्राकृतिक आपदाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मानव जा रहा है कि वर्तमान में बढ़ती आपदाओं के पीछे विकास के नाम पर अंधाधुंध निर्माण कार्य है। यानि ये आपदायें प्राकृतिक न होकर मानव निर्मित ही हैं। पिछले समय में तेजी से हो रहे हैं इस प्रकार के विनाश के मद्दनजर यह विचार करना जरूरी हो गया है कि मानव के लालच से प्रेरित तथाकथित विकास को इस प्रकार से जारी नहीं रखा जा सकता। इस प्रकार के जर्जर एवं नाजुक पहाड़ पर अनियंत्रित निर्माण कार्य ही जोशीमठ के धंसने का कारण है। और तरलबव है कि जोशीमठ के पहाड़ की तलहटी में जिस प्रकार से जरूरत से ज्यादा चौड़े चार धाम मार्ग के निर्माण हेतु पहाड़ को कटा गया और एनटीपीसी द्वारा अपनी हाइड्रो परियोजना के लिए पहाड़ के बीच में से एक सुरंगनिकाली गई, उससे इस नाजुक पहाड़ पर प्रभाव पड़ना एक स्वाभाविक बात मानी जा रही है। उस क्षेत्र का



जायजा लेने के बाद यह बात भी ध्यान में आती है कि वहाँ ऊंचे ऊंचे होटलों एवं इमारतों के निर्माण और सेनिटेशन की ठीक व्यवस्था न होने के चलते इस जर्जर क्षेत्र की अस्थिरता और बदल गई। इस सबके चलते आज जोशीमठ का पूरा क्षेत्र ही धंसता जा रहा है और उसे बचाने का कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। सबाल सिर्फ जोशीमठ का नहीं है। विकास के नाम पर संपूर्ण उत्तराखण्ड में निर्माण कार्य और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ लगातार जारी है। पेड़ों के कटने के कारण पहाड़ों पर हारियाली समाप्त हो चुकी है और इसके कारण मिट्टी वाले इन पहाड़ों से भूस्खलन एक सामान्य प्रक्रिया बन चुकी है। पूरे उत्तराखण्ड और खासतौर पर पर्यटन आकर्षण के केंद्र जैसे नैनीताल और मसूरी आदि भी विनाश के कागर पर खड़े हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जोशीमठ जैसा स्थिति की पुनरावृत्ति नैनीताल में भी हो सकती है।

बिनासोचे-समझेनिर्माणकार्य: गौरतलब है कि उत्तराखण्ड में सड़कों का चौड़ीकरण, सुरंग निर्माण, रेलवे लाईन, बांध निर्माण आदि इनकास्ट्रक्चर और इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर भवन निर्माण, जिसमें अधिकांशतः होटल निर्माण शामिल है, का काम पिछले दो दशकों में तेजी से बढ़ा है। इस दौरान केन्द्र और राज्य में अलग-अलग पार्टीयों की सरकारें रही हैं। इसलिए किसी एक पार्टी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि हिमालय पर्वत तुलनात्मक तृप्ति से नए पर्वत हैं और इसलिए यह जर्जर और नाजुक हैं। इसकी धारण क्षमता से ज्यादा इसमें बर्डू छेड़छाड़ यहाँ भूस्खलन एवं धूधसाव का कारण बनती है। ऐसे स्थिति के चलते इस क्षेत्र में नए निर्माण स्थाई नहीं रह सकते और वर्तमान स्थिति में तो ऐसा देखा जा रहा है कि निर्माण के दौरान ही

ओपीएस के साथ जिम्मेवारियां भी बढ़ी

13 नवंबर 2022 का लाहौड़ा के पावन अवसर पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपनी प्रथम कैबिनेट की मीटिंग में हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बहुचर्चित व लंबित मांग पुरानी पेशन को बहाल करके प्रदेश के करीब 126000 कर्मचारियों के बुधपे को सहारा देकर एक नया इतिहास रचा है। कांग्रेस पार्टी ने गत वर्ष विधानसभा चुनावों में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेशन बहाल करने की मांग प्रमुखता से उठाई थी। प्रथम कैबिनेट की मीटिंग में इसकी बहाली करके अन्य राज्य के कर्मचारियों के लिए भी एक उदाहरण पेश किया है। वर्तमान हिमाचल प्रदेश सरकार पर करीब 75000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके अलावा कर्मचारियों का एरियर, भर्ते इत्यादि अनेकों देनदारी अभी भी लंबित पड़ी है जिस पर करीब 11000 करोड़ रुपए का खर्च होना प्रस्तावित है। ऐसी वितरित आर्थिक परिस्थितियों में भी श्री सुखविंदर सिंह सुखवुर सरकार ने अपने प्रदेश के कर्मचारियों के आने वाले भविष्य को बेहतरीन, सुखद व समृद्ध बनाने का इतिहासिक निर्णय धरातल पर उतारा है। जिस प्रदेश या घर का मुखिया अपने बायदों तथा जिम्मेदारियों को अपनी कार्यशैली में भी अमल में लाए तो उस प्रदेश तथा घर की खुशहाली,

A photograph showing a person's hand holding a magnifying glass over a document. The document has the word "PENSION" printed in large, bold, red capital letters. The background shows some text and a small illustration of a person's head.

हिमाचल प्रदेश विधानसभा युवान वर्ष 2022 में कांग्रेस पार्टी को 68 सीटों में से 40 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। कांग्रेस पार्टी को सत्ता 0.90 फीसदी अंतराल से प्राप्त हुई थी। भारतीय जनता पार्टी को 43 फीसदी मत तथा कांग्रेस पार्टी को 43.90 फीसदी मत प्राप्त हुए थे। कांग्रेस पार्टी को सत्तासीन करने के पीछे प्रदेश के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग कांग्रेस के लिए संजीवनी बृती का काम कर गई थी। यही कारण है कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट की मीटिंग में कर्मचारियों की बड़ी मांग को बड़ी सजगता के साथ सुलझाया। कर प्रदेश के कर्मचारियों को प्रदेश के बेहतरीन भविष्य के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार का यह निर्णय अन्य राज्यों की सरकारों के लिए भी प्रेरणा दोता बनेगा क्योंकि हिमाचल से ज्यादा समृद्ध कई अन्य राज्य हैं, जो कि अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के इस निर्णय से कर्मचारी पूर्ण तन्यता, विश्वसनीयता, ईमानदारी तथा कर्तव्यनिष्ठासे अपने कार्यों को करने के लिए सुदृढ़ होंगे। वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा कर्तव्यवस्था परिवर्तन करना का जो नारा बुलंद किया है उसके पीछे प्रदेश के कर्मचारी एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। प्रदेश का कर्मचारी पूरी लगन, मेहनत तथा ईमानदारी के साथ सरकार की योजनाओं तथा कार्यों को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए लग जाए तो निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार

आने वाले समय में नए आयाम स्थापित कर सकती है। अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल करके अपनी जिम्मेदारी को निभा दिया है। अब कर्मचारियों को भी प्रदेश के आम जनमानस के लिए कार्य करने के लिए पूर्ण ईमानदारी के साथ जुट जाना होगा। वर्तमान सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था करना होगा। सरकार के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के बेतन, भत्ते तथा पेंशन पर चला जाएगा ऐसे में समाज के अन्य वर्गों के कल्याण के लिए भी सरकार को राज्य में उपलब्ध संसाधनों के बेहतरीन दोहन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जिसमें प्रदेश का कर्मचारी तथा अधिकारी वर्ग की भूमिका भी अग्रणीय होगी। प्रदेश सरकार को पर्यटन, कृषि, पन विद्युत, सौर ऊर्जा तथा औद्योगिकरण से प्रदेश की आर्थिकी को सुधारना होगा। जिसमें बाहरी निवेशकों की अहम भूमिका होगी। प्रदेश में अनेकों ऐसे डिस्ट्रिक्टेशन उपलब्ध हैं, यदि उनका उत्थान बाहरी निवेशकों के माध्यम से किया जाए तो भी प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश का शांत व स्वास्थ्यवर्धक वातावरण, गगननुंबी पहाड़ियां, हसीन वादियां, स्वच्छ नीर तथा प्राकृतिक कृषि के लिए समृद्ध भूमि इत्यादि संसाधन बाहरी निवेशकों के लिए आर्कषण का कंद्र सदैव बने हुए हैं। प्रदेश सरकार को बाहरी निवेशकों को बेहतरीन सुविधाएं दे करके इनके दोहन की एक पारदर्शी तथा समयबद्ध नीति लानी होगी। यदि प्रदेश की आर्थिक स्थिति सरकार के नियंत्रण में आ गई तो निश्चित तौर पर प्रदेश की आम जनता का भविष्य भी सुनहरे मार्ग को प्रशस्त करेगा।

वार्षिक गोपनीय

पॉक्सिफ़ॉम के ताजा आंकड़ों ने भारत में बढ़ती आर्थिक असमानता को उजागर कर दिया है

हम भारती

खुश हात रहत है कि भारत शाप्रहा
या की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। लेकिन
या के इस तीसरे सबसे बड़े मालदार देश की असली
तत्वत्वत क्या है? इस देश में गरीबी भी उतनी ही तेजी से बढ़ती
रही है, जिनती तेजी से अमीरी बढ़ रही है। अमीर होने
में की संख्या सिफ़र सैक़ड़ों में होती है लेकिन गरीब होने
में की संख्या करोड़ों में होती है। ऑक्सफ़ॉम के ताज़ा
करोड़ों के मुताबिक पिछले दो साल में सिफ़र 64 अरबपति
है। सिफ़र 100 भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 54.12
बिलकुल रु. है यानि उनके पास इन्हाँ पैसा है कि वह
उत्तर सरकार के डेढ़ साल के बजट से भी ज्यादा है। सारे
बपतियों की संपत्ति पर मुश्किल से 2 प्रतिशत टैक्स

देश दुनीया से

सियासों होड़ में धूल चाटती परंपराएं
मंदिरों के शहर मुद्रे के अवनीपुरम अखाड़े में सांडों खुला छोड़ दिया गया, चमकदार सींगों और फॉन्ट नथुनों वाले दौड़ते गुस्सैल सांडों या बैलों को वश में करने के लिए भी खतरनाक ढंग से उनके पीछे दौड़ने लगे। ध्यान रहे, 2011 आंदोलन के बाद जल्लीकट्टू को पूरे देश में तमिल गौरव और संस्कृत के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इसे वीरता का खेल कहा जाता है। यह खेल कभी-कभी हिंसक भी हो जाता है, हर साल एकाधिक जान गंवाते हैं और सैकड़ों घायल हो जाते हैं। घायलों में तमाशा और राहगीर भी शामिल रहते हैं। वैसे यह स्तंभ जल्लीकट्टू पर बैठनहीं है, बल्कि तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि और मुख्यमंत्री के स्टालिन के बीच चल रही सियासी होड़ पर है। राज्यपाल, 19 संविधान का रक्षक माना जाता है और प्रशासन के मुखिया, मुख्यमंत्री जो कार्यपालिका का संचालन करते हैं, दोनों के बीच चल रही लड़ाई भी जल्लीकट्टू से कुछ कम नहीं है। पिछले सप्ताह तमिलनाडु में विधानसभा के फर्श पर भले ही लाहू न गिरा हो, पर सुस्थापित संसदीय परंपराएँ और रिवाजों को रौद्र दिया गया। विधानसभा के बाहर तो और भी झगड़े होते हैं, जहां दोनों पक्षों ने परस्पर ऐसे ताबड़तोड़ हमले बोले बुरी स्थिति बन गई। 9 जनवरी को राज्यविधानसभा के उद्घाटन के पहले दिन हंगामा तब शुरू हुआ, जब राज्यपाल रवि ने पारंपरिक अभिभाषण पढ़ना शुरू किया। द्रमुक के विधायक पिछले सप्ताह समारोह में तमिलनाडु का नाम बदलकर तमिलाजगम करने के

राज्यपाल के सुझाव से नाखुश थे, उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नारे लगाए। उन्होंने महसूस किया कि राज्यपाल केंद्र की ओर से राजनीति करते हुए हवें पार कर रहे हैं। राज्यपाल अंग्रेजी में पहले से लिखित भाषण पढ़ रहे थे। मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट सहयोगियों ने गौर से सुनेने पर उनके कथन और लिखित भाषण में अंतर पाया। राज्यपाल ने न सिर्फ कुछ पैराग्राफ छोड़ दिए थे, बल्कि कुछ ऐसी चीजें जोड़ दी थीं, जो भाजपा और केंद्र सरकार के साथ जुड़ी थीं। मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों ने चर्चा करके एक योजना बनाई, जिसे उन्होंने तब क्रियान्वित किया, जब अभिभाषण का तमिल संस्करण राज्यपाल की ओर से विधानसभा अध्यक्ष पढ़ रहे थे। मुख्यमंत्री ने जल्दी पिछले सप्ताह तमिलनाडु में सदन के फर्श पर भले ही लहू न गिरा हो, पर सुस्थापित संसदीय परंपराओं और रियाजों को रौंद दिया गया। विधानसभा के बाहर तो और भी भद्दे झगड़े हुए हैं, जहां दोनों पक्षों ने परस्पर ऐसे ताबड़तोड़ हमले बोले कि बुरी स्थिति बन गई। 9 जनवरी को राज्य विधानसभा के उद्घाटन सत्र के पहले दिन हंगामा बत शुरू हुआ, बज राज्यपाल रवि ने पारंपरिक अभिभाषण पढ़ना शुरू किया। द्रमुक के विधायक पिछले सप्ताह एक समारोह में तमिलनाडु का नाम बदलकर तमिजागम करने के राज्यपाल के सुझाव से नाखुश थे, उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नारे लगाए।

हा एक प्रस्ताव तयार किया, जिसम मूल भाषण का बिना किसी बदलाव के बनाए रखने की मांग की गई। जब अध्यक्षतमिल संस्करण पढ़ने के बाद वैटे, तब मुख्यमंत्री ने अपने प्रस्ताव को तत्काल आगे बढ़ा दिया। सामान्य हालात में राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद राष्ट्रगान होता है और उस दिन की कार्यवाही स्थगित हो जाती है। मूल लिखित भाषण को बहाल करने वाले प्रस्ताव को पढ़ना मुख्यमंत्री के लिए असामान्य था। कैसा अभूतपूर्व समय था, जब कार्यवाही औपचारिक रूप से संपन्न घोषित नहीं की गई थी और राज्यपाल ने बहिर्भासन कर दिया! बेशक, उच्च संस्थानों की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रोटोकॉल और नियम-कायदे तैयार किए जाते हैं। उम्मीद की जाती है कि जो लोग इन ऊंचे संस्थानों में पहुंचेंगे, वे विपरीत हालात का सामना करने में पर्याप्त सूझ-बूझ दिखाएंगे और संयम बरतेंगे। साफ तौर पर उस दिन ऐसा नहीं हुआ। राज्यपाल को जब पता चला कि उनके द्वारा बदले गए अंशों को विधानसभा के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, तो वह सदन से बाहर निकल गए। वैसे, संविधान में ऐसा कुछ नहीं है, जो राज्यपाल को जो कुछ भी दिया गया है, उसे पढ़ने के लिए बाध्य करता हो। यह मात्र संसदीय परंपरा रही है कि राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित भाषण ही पढ़ते हैं। पहले भी ऐसे उदाहरण सामने आए हैं, पर पहले किसी भी राज्यपाल ने बहिर्भासन नहीं किया था। यह विवाद तब और गहरा गया, जब घटना के तुरंत बाद राजभवन से सूचना लीक हो गई, जिसमें दावा किया गया कि सरकार द्वारा भेजे गए लिखित भाषण को राज्यपाल का अनुमोदन नहीं है। दावा किया गया कि राज्यपाल ने भाषण में बदलाव के सुझाव दिए थे, पर तब तक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अभिभाषण ही छापाई के लिए चला गया था, पाठ में संशोधन के लिहाज से बहुत देर हो चुकी थी।

राजस्थान में कांग्रेस फिर बनाएगी सरकार : पायलट

बीकानेर (हिस.)। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि विधानसभा चुनाव में अब दस महीने रह गए हैं। 26 जनवरी से शुरू हो रहा हाथ से हाथ जोड़े कार्यक्रम ब्लॉक, जिला व प्रदेश लेवल पर चलेगा। इस पर लगातार काम कर रहे हैं। इस दौरान क्षेत्र, जिलों में जाकर लोगों को एकत्रित करके संगठित करेंगे और समय रहते पांच साल भाजपा, पांच साल कांग्रेस वाली पुरानी परिपाटी को तोड़ते हुए कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मंगलवार को हनुमानगढ़ के लिए रवाना होने से पहले मीडियाकर्मियों से बातचीत में सचिन पायलट ने कहा कि सरकार, संगठन, कार्यकर्ता-नेता एक साथ काम करेंगे तो निश्चित इस बार पुरानी परिपाटी टूट जाएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक प्रश्न के उत्तर में पायलट ने कहा कि राहुल गांधी वर्तमान में देश में घुल रही कड़वाहट, समाज में पैदा हुआ टकराव के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें प्रतिशोध का माहौल है। यह यात्रा महांगड़ और बेरोजगारी के खिलाफ भी है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन आज



मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आधारों का जयपुर प्रथम डॉ. विजय सिंह फौजदार ने बताया कि 18 जनवरी को चिकित्सा संस्थानों पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के आयोजन में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें गर्भ में पल रहे शिशु और स्वयं की देखभाल के बारे में बताते हुए पोषण युक्त आहार के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसमें गर्भवती महिलाओं के हिमोगलोबिन, ब्लड प्रेशर, शुगर, लंबाई, एचआईवी, सिफलिश आदि जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं को गुणवत्ता युक्त प्रसव पूर्व जांच सुविधाएं देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया जाता रहा है, जिससे गर्भावस्था व प्रसव के दोनां जोखिम को कम करने में मदद मिल सकेगी। अभियान में सभी आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं निश्चल प्रदान की जा रही हैं।

होशियारपुर पहुंची भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी बोले- कांग्रेस के टॉप एजेंडे में किसान



चंडीगढ़ (हिस.)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि किसान हमेशा से कांग्रेस के टॉप एजेंट पर रहा है। पंजाब व केंद्र में कांग्रेस की सत्ता आने पर किसानों को एमएसपी समेत कई रियायतें प्रदान की जाएंगी। भारत जोड़े यात्रा के छठे दिन होशियरपुर में पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए की सरकार में किसानों के लिए कई योजनाएं लागू की गईं, लेकिन जितना काम किसानों के लिए होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। पंजाब समेत पूरे देश में कृषि को बचाने के लिए किसानों को इस

समय बढ़े राहत पैकेज दिए जाने की जरूरत है। वरुण गांधी के साथ एक मंच पर आने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि वरुण गांधी ने संघ की जिस विचारधारा को अपनाया है, वह उस विचारधारा को नहीं अपना सकते। पंजाब सरकार पर कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब के लोगों ने कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का बड़ा मौका दिया, लेकिन आप सरकार पंजाब को अभी तक कोई विजय नहीं दे पाई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार के सत्ता में आने पर पंजाबी किसानों को लंबे समय के लिए एक स्थाई वेजन दिया जाएगा। राहुल ने कहा कि पंजाब को नब तक पंजाब से नहीं चलाया जाएगा, तब तक पंजाब के लोगों का भला नहीं हो सकता। पंजाब की वृद्ध कांग्रेस सरकार के कार्यकाल पर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पिछले चुनाव के दौरान सत्ता विरोधी लहर थी। इस वजह से कांग्रेस को हार का सामन करना पड़ा, लेकिन बहुत जल्द कांग्रेस

चंडीगढ़ नगर निगम में आठवें साल भी भाजपा का कब्जा

मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर पदों पर मिली जीत चंडीगढ़ (हिस.)। चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर पद पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है। सांसद किरण खेर की एक वोट के बल पर भाजपा ने यहां मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर तथा डिप्टी मेयर के पदों पर कब्जा किया है। कांग्रेस तथा शिरोमणि अकाली दल के पार्षदों ने इस चुनाव का बहिष्कार करते हुए भाग नहीं लिया। चंडीगढ़ में मेयर का कार्यकाल एक साल का होता है। यहां कुल 35 सीटों में से वर्तमान में भाजपा के पास 14, आम आदमी पार्टी के पास 14, कांग्रेस के पास छह तथा शिरोमणि अकाली दल के पास एक पार्षद है। यहां एक वोट सांसद का है। इस वर्ष मेयर पद के लिए भाजपा ने अनूप गुप्ता तथा आम आदमी पार्टी ने जसबीर सिंह को उतारा। भाजपा के अनूप गुप्ता को 15 तो आम आदमी पार्टी के जसबीर सिंह को 14 वोट मिले। एक वोट के अंतर से भाजपा ने मेयर पद का चुनाव जीत लिया। इसी प्रकार सीनियर डिप्टी मेयर के लिए भाजपा के कंवरपाल राणा व आप की तरुण मेहता के बीच मुकाबला था। इस पद पर भी भाजपा के कंवरपाल राणा को जीत मिली। उधर, डिप्टी मेयर पद के लिए भाजपा के हरजीत सिंह ने आप की सुमन सिंह को हरा दिया। निगम कार्यालय में आज सुबह 11 बजे चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने नामजद पार्षदों के हाल में बैठें को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। आप पार्षदों का आरोप था कि नामजद पार्षदों को यहां बिठाने से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होगी। इसे लेकर काफी देर हंगामा चलता रहा। निर्वाचन अधिकारी द्वारा रूल बुक दिखाए। जाने के बाद मेयर पद के लिए चुनाव शुरू हुआ। सबसे पहला वोट चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर ने डाला। उसके बाद अन्य पार्षदों ने वोट डालने वोट डालते समय आप के पार्षदों ने बैलेट पेपर पर स्थानीय लगे होने का तर्क देते हुए विरोध जताया। चंडीगढ़ नगर निगम में लगातार आठवें साल भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर बनाया है। साल 2015 के बाद से कांग्रेस का कोई भी मेयर नहीं बन पाया है। भाजपा वर्ष 2016 से लगातार मेयर बनाती ही आ रही है। यहां पिछले साल हुए आम मतदान में भाजपा व आप दोनों को एक समान सीटें मिली थी। चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार करने वाली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एच.एस.लक्कवाली ने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस से मेयर चुनाव से वॉकआउट कर चुकी है। कांग्रेस ने साफ किया है कि वह विपक्ष में बैठ कर शहर की जनता के मुद्दों को उत्तरी रहेगी। पार्टी के सभी छह पार्षद शहर से बाहर हैं चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर समेत तीनों पदों पर भाजपा के कांबिज होने के बाद सांसद किरण खेर ने नई टीम को बधाइया देते हुए कहा कि बगैर किसी भेदभाव के शहर का विकास

किसानों का फैसला, 20 जनवरी
को शुगर मिल पर लगाएंगे ताला



यमुनानगर (हि.स.)।
भारतीय किसान यूनियन
चढ़ूनी के बैनर तले
जगाधरी अनाज मंडी में
मंगलवार दोपहर को एक
गर मिलों को बंद करने का
पत्र कारों को बताया कि कल
ठक होनी थी, लेकिन कृषि
माफ पता चलता है कि वह
ने कहा कि संगठन के सभी
कर किसानों से गन्ना छिलाई
संगठनों से अपील करते हुए
के दाम को लेकर अपने हक
किसान एक जुट होकर 20
ल लेकर सरस्वती शुगर मिल
गर मिल का गेट बंद किया
का रेट नहीं बढ़ाती तब तक
किया जाएगा। इस मौके पर
बीर प्रदेश सहित बड़ी संख्या

क्लब 11 ने स्मैशर्स क्रिकेट क्लब को दी मात्र किसानों ने चूरु कलेक्टर के बाहर किया प्रदर्शन



जम्मू। नगरोंता खेल गांव में निर्भय भारत फाउंडेशन के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस टी-20 कि केट कप का उद्घाटन किया गया, जिसमें उद्घाटन मैच में प्रैस क्लब 11 ने स्पैशर्स क्रिकेट क्लब को 20 रन के अंतर से रोमांचक मुकाबले में मात दी। टूर्नामेंट का उद्घाटन तरुण उपल चंद्रमैन निर्भय भारत फाउंडेशन और सुनील भगत द्वारा किया गया जो इस अवसर पर मुख्यातिथि व विशेष के अतिथि के तौर पर शामिल हुए। टूर्नामेंट का नारा है ड्रग्स को ना, खेलों को हां हाँ। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए तरुण उपल ने कहा कि इस आयोजन का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और ड्रग्स और अन्य संबद्ध सामाजिक गतिविधियों के शिकार होने से युवाओं को बचाने हैं ताकि वह खेल गतिविधियों में अधिक से अधिक भाग लेकर नशों जैसी बुराइयों से बच सकें। उन्होंने कहा कि खेल गांव जम्मू में एक खेल केंद्र बन गया है और इसके क्षेत्र में मेंगा कार्यक्रम आयोजित करने से नवोदित खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का पर्याप्त अवसर मिलता है। मैच में अंपायर के रूप में सचिन सिंह और सुनील थापा रहे। जबकि टूर्नामेंट मुख्य आयोजक नवीन कौल (खेल सचिव, निर्भय भारत फाउंडेशन) की देखरेख में आयोजित किया जा रहा है।

जैसलमेर में छह पाक विस्थापितों को सौंपी गई भारतीय नागरिकता



जैसलमेर (हि.स.)। जैसलमेर में पाकिस्तानी विस्थापितों को के सम्बन्ध में एक दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। मंगलवार

डीआरडीए सभाकक्ष में आयोजित नागरिकता प्रमाण-पत्र प्रदान किए
शिविर में जिला कलक्टर टीना डाबी इस दौरान दस्तावेज की कार्रवाई

जयपुर लिटरेचर फैस्टिवल कल से

जयपुर (हिंस.)। दुनिया के सबसे
करिस्माई लिटरेचर फेस्टिवल का
आयोजन 19 से 23 जनवरी को
गुलाबी नगरी जयपुर के होटल
क्लार्क्स आमेर में होने जा रहा है।
इस साल फेस्टिवल के 16वें संस्करण में
विज्ञान, तकनीक और एआई की
दुनिया के विशेषज्ञ इन जटिल विषयों
पर रोशनी डालेंगे। प्रोग्राम की
विविधता के साथ फेस्टिवल के एक
सत्र में पुरस्कृत खोजी पत्रकार विद्या
कृष्ण से वस्कुलर सर्जन और लेखक
अच्छीरेश सात्किव संवाद करेंगे। सत्र
के दौरान कृष्ण अपनी नई किताब
फैन्टम ल्प्गे हात ट्यूबरक्लोसिस शेप्ड
आवर हिस्ट्री के माध्यम से बतायेंगे
कि विभिन्न बीमारियों के उपचार ने
कैसे मानवजाति को प्रभावित कर
विकास में योगदान दिया। एक अन्य
सत्र में, जाने-माने कैंसर चिकित्सा
विज्ञानी जीवविज्ञानी और पुलित्रूप
पुरस्कार से सम्मानित लेखक सिद्धार्थ
मुखर्जी अपनी नई किताब, द सोंग
ऑफ द सेल के माध्यम से हमारे
अंगों की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण
ईकाई के बारे में बताएंगे।

No. SSUHS/47/2010/

NOTICE INVITING QUOTATION

Sealed quotation affixing court fees Stamp of Rs 8.25 (Rupees Eight and Twenty Five paisa) only are invited from authorized dealer/ supplier for supply of the following item for office use at Srimanta Sankaradeva University of Health Sciences.

The quotation complete in all respect is to be submitted on or before **02.02.2023** upto 2:00 PM and the same will be opened **02.02.2023** at 3:00 PM

SL.	Parameter	Minimum Required Specification
------------	------------------	---------------------------------------

A.	PRINT :	
1.	PRINT SPPED (A4) (Mono/Color)	25 PPM or higher
2.	Print Resolution	1,200 ×1,200 dpi or better
3.	First Print Out Speed	7 second of less
4.	Paper Weight	52-300 gsm or more
B.	SCAN :	
1.	DADF	
1.	Scanning Speed (Simplex)	48 ipm or more
2.	Scanning Speed (Duplex)	15 ipm or more
3.	Scan Resolution	600 dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi 200×400dpi, 200×100dpi
4.	File Format Supported	TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JPG compression/ High-compression PDF), PDF/A, Encrypted PDF
5.	Transmission Type	Scan to SMB; Scan to E-mail; Scan to FTP to FTP over SSL; Scan to USB; TWAIN Scan; WSD Scan
C.	COPY FUNCTION:	
1.	Copy size / Copy Resolution	Max. A3×600 × 600 dpi or better
2.	Zoom Ratio	25%-400%
D.	Other Common Parameters	
1.	Warm up Time	18 Second or less
2.	Duplex Printing	Yes Required
3.	Paper Tray	2 (Two) Cassette Cassette 2 : 500 Sheets Cassette 2 : 500 Sheets
4.	Multi Purpose Tray	100 Sheets
5.	Maximum Paper Sheet Supported in the Machine with addition of additional trays	More than 6500 Sheets
6.	SSD / HDD Capacity	SSD : 32 GB/HDD 320 GB (Optional)
7.	Out put Tray	Max. 500 Sheets + 100 sheets face-down
8.	Power Consumption Range	500-700 Wait
9.	Control Panel	10 Inch or large Screen
10.	Noise (ISO7779/ISO9296 During Printing/Copy	67 dB(A)
11.	Processor Speed	1 GHz or more
12.	Memory (RAM)	4 GB or more
13.	Ports	USB 2.0 High Spped × 1, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T
14.	Toner Yielding Capacity	20,000 Pages or more
15.	Stabilizer	2 KVA Stabilizer
16.	Trolley	Trolley
17.	Warranty	1 Years Comprehensive On site

- Terms & Conditions :**

 1. The price of items is to be quoted inclusive/exclusive of all taxes as applicable.
 2. The copies of GST registration, Trade Licences, Pan Card to be annexed with the Quotation.
 3. The bill/bills to be submitted in duplicate.
 4. The bills to be produced for payment only after successful and satisfactory supply of the item.
 5. The undersigned has every right to accept and reject the quotation as deemed fit it

proper.

राष्ट्रसेवा में समर्पित

सुनील कुमार ने बतौर
उप-कमाण्डेंट 100
आर.ए.एफ. बटालियन
में गुजरात में तैनाती के
दौरान गोधाकांड के
उपर्युक्त भड़के हिस्क
दंगों को अपनी टीम के

**प्रशिक्षण के समय अनुभव का प्रयोग करते हुए
सूत में 48 घंटे के भीतर कानून एवं व्यवस्था को
बहाल करने में अहम भूमिका निभाई, जिसकी
प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी
तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात
द्वारा की गई।**

सितम्बर, 1968 को बिहार राज्य के भागलपुर जिले में जन्मे पटना निवासी सुनील कुमार (पुत्र स्व. रामबृश प्रसाद एवं शान्ति देवी) ने स्थातक उपाधि प्राप्त करने के उपरान्त, भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे पुराने एवं बड़े आंतरिक सुरक्षा बल यानि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी के तौर पर दिसम्बर 1994 से बतौर सहायक कमाण्डेंट अपनी सेवाएं प्रारम्भ की तथा अपने इस 28 वर्षों से अधिक के सेवाकाल के दौरान देश के विभिन्न दुर्गम/अतिदुर्गम/कठिन एवं अशांत क्षेत्रों चाहे वह उग्रवाद से ग्रसित पूर्वोज्जर क्षेत्र हो या जम्मू एवं कश्मीर या नज़सलवाद से ग्रसित एल.डज्ल्यू.ई. का एरिया हो या कानून एवं व्यवस्था से ज़ूझ रहे देश के अन्य क्षेत्र हों, में विभिन्न पदों पर तैनात रहकर समवाय एवं बटालियनों का केन्द्रीय रिवर्ज पुलिस बल के मापदण्डों के अनुसार कुशल नेतृत्व के द्वारा के.रि.पु. बल एवं देश की गरिमा को उच्चतम स्तर पर ले जाने का सफल प्रयास किया है।

श्री कुमार ने बतौर उप-कमाण्डेंट 100 आर.ए.एफ. बटालियन में गुजरात में तैनाती के दौरान गोधारा काण्ड के उपरान्त भड़के हिंसक दंगों को अपनी टीम के साथ कुशल नेतृत्व, व्यावसायिक दक्षता व प्रशिक्षण के समग्र अनुभव का प्रयोग करते हुए सूरत में 48 घण्टे के भीतर कानून एवं व्यवस्था को बहाल करने में अहम भूमिका निभाई, जिसकी प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात द्वारा की गई। वर्ष 2001 में गुजरात में आये विनाशकारी भूकम्प के दौरान अहमदाबाद में श्री कुमार ने

श्री कुमार जो
कि वर्तमान में मध्य सेंटर मुख्यालय
के.रि.पु. बल लखनऊ में पुलिस उप-
महानिरीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं
दे रहे हैं, ने अपने दाईं दशकों से
अधिक के शानदार कैरियर में,
ज्यादातर देश के आतंकवाद, उग्रवाद
एवं नज़सल प्रभावित प्रान्तों जैसे
जम्मू-कश्मीर, असम, उड़ीसा,
बिहार, नागालैंड, त्रिपुरा, गुजरात और
छातीसगढ़ जैसे अतिरुद्धार्म, कठिन एवं
अशांत क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर तैनात
रहकर अपनी व्यावसायिक दक्षता व
कुशल नेतृत्व के द्वारा देश की एकता
एवं अखण्डता को कायम रखने हेतु
अपनी बेहतरीन सेवाएं इस देश के
लिए दी है।

अपनी टीम के साथ मिलकर¹
अपनी जान जोखिम में डालते हुए
74 नागरिकों की अमृत्यु जान बचाई
जिसकी सराहना स्थानीय प्रशासनिक
अधिकारियों के साथ-साथ केन्द्रीय
रिजर्व पुलिस बल के उच्चाधिकारियों
द्वारा भी की गई।

श्री कुमार द्वारा बताए कमाण्डेंट
देंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जैसे
नज़सल प्रभावित क्षेत्र में शांति
व्यवस्था कायम करने की कमान
संभाली तथा अपनी परिचालनिक
दक्षता एवं व्यावसायिक कार्य-
कुशलता को साबित करते हुए बिना
किसी जान-माल व सरकारी सम्पत्ति
की क्षति के नज़सलवाद के विरुद्ध
सफलतापूर्वक अधियान चलाकर



ਪੁਲਿਸ ਤਪ-ਮਹਾਨਿਈਕਾਂ, ਕੇ.ਏ.ਪੁ. ਬਲ

शांति कायम किया तथा नज्मलवाद से ग्रसित दूर-दराज इलाके के भटके हुए युवाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का सफल प्रयास किया गया। माता वैष्णो देवी दरबार की सुरक्षा के साथ-साथ कटरा शहर को व्यापक सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैरगं 6 बटालियन के रि.प. बल की

म लान का सफल प्रयास किया गया।
 श्री कुमार ने दक्षिण बस्तर दंतवेड़ा में अवस्थित प्राचीन और ऐतिहासिक पर्यटन नगरी बारसूर की खोई हुई विरासत एवं प्रसिद्धि को फिर से स्थापित करने की पहल करते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी को बारसूर में ऐतिहासिक महत्व के अवशेषों को बहाल करने के लिए पत्र लिखकर की। इस प्रकार श्री कुमार ने अपने सकारात्मक और निःस्वार्थ प्रयासों के जरिये ऐतिहासिक पर्यटन शहर बारसूर की खोई हुई प्रसिद्धि को स्थानीय प्रशासन एवं सम्मानित लोगों के सहयोग से पुनः स्थापित किया। जिला प्रशासन

उन्‌हाँ रक्षा की पानी गर्ता प्रशासन
व छज्जीसगढ़ पर्थिन बोर्ड के सहयोग
से बजीसा मंदिर परिसर में पहला
बारासूर महोत्सव आयोजित किया
गया जिसकी सराहना शासन एवं
प्रशासन के पदाधिकारियों एवं
स्थानीय लोगों द्वारा की गयी।
इसी अनुकूल में देश के मालमे

इसी अनुक्रम में देश के सबसे संवेदनशील तीर्थ स्थलों में से एक वैष्णो माता दरबार श्राइन बोर्ड के साथ-साथ देश के विभिन्न प्रान्तों से

अये श्रद्धालुओं की सुरक्षा व उनकी हर प्रकार से मदद के लिए सैदव तपतरता के साथ कार्य किया। श्री वैष्णो माता दरबार में भव्य जागरण का शुभारंभ श्री कुमार के नेतृत्व में किया गया और इनके पदास्थापित रहने तक 4 बार कटरा

चलाकर शान्ति व्यवस्था को कायम रखा। इसी दौरान पूर्वोज्जर में उत्पन्न

वस्था अवरुद्ध (Eco-Blockade) स्थिति को गत व राणीति से संभाला परिणामस्वरूप कोई घटना नहीं हुई। इसके साथ ही श्री ने मणिपुर राज्य के भाग चुनाव के दौरान 3 जिलों पश्चिम चुनाव के दौरान 2 के नोडल अधिकारी की दारियों का निवार्हन पूर्वक बिना किसी व्यवधान व सम्पन्न कराने में अहम निशाई।

कुमार मां वैष्णो देवी सेवा पटना से पिछले कई वर्षों से कर समाजसेवा के कार्यों में अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं। नुक्रम में उहोंने मां वैष्णो वा समिति, पटना के सहयोग कांक 7 फरवरी, 2022 को गोरथाना इलाके के गोला ब्रह्मस्थान मंदिर के मां ज्ञालड सेंटर का शुभारंभ किया जो पूरी तरह से नैन यल है। मां ज्ञालड सेंटर द्वारा मिया, हीमोफाइलिया और टक एनीमिया सहित समाज

के बेहद निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों को निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त यह संस्था प्रत्येक वर्ष आर्थिक रूप से कमज़ोर कन्याओं की शादी कराने में भी अन्य लोगों को भी समाज सेवा हेतु प्रेरित करते हैं। अपने सरल एवं सुशील स्वभाव से परिपूर्ण श्री कुमार सदैव देश एवं समाज के जरूरतमंदों को यथोचित मदद करने में सदैव

सहभागिता करती है।
 श्री कुमार एक प्रतिभावान, कर्मठ, ईमानदार एवं सक्रिय पुलिस अधिकारी होने के साथ-साथ एक सहदेवी एवं समाज सेवक के रूप में भी किसी से पीछे नहीं हैं। श्री कुमार समाज के असहाय एवं अत्यन्त गरीब बच्चों के उत्थान हेतु कार्य कर रहीं समाजसेवी संस्थानों से भी जुड़े रहकर उनके उत्थान में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं तथा समाज के अपने आप को प्रथम पक्षि में स्थापित रखते हैं।
 श्री कुमार को उनके कुशल नेतृत्व एवं सराहनीय सेवाओं के लिए अब तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के उच्चाधिकारियों के साथ-साथ सम्बंधित तैनाती क्षेत्रों के शासन एवं प्रशासन के उच्चाधिकारियों द्वारा कुल 119 प्रशस्ति पत्रों/डिस्क एवं उत्तम प्रबलियों से सम्मानित/अलंकृत किया जा चुका है। ○○○

वीरता, साहस और बलिदान का पर्याय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

भा रत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। सीआरपीएफ की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्रवाई आंदोलनों एवं राजनीतिक अशांति तथा साम्राज्यिक नीति के रूप में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में लगातार सहायता करने की इच्छा के महेनजर, 1936 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मद्रास संकल्प के

आजादी के बाद 28 दिसम्बर, 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा इस बल का नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिया गया था। तत्कालीन गृहमंत्री सरदार बल्लभ भाईं पटेल ने नव स्वतंत्र राष्ट्र की बलात्मकता उनकरणों के अनुगमन द्वारा बल के लिए प्रकृत आगामी प्रगति की कलाना की थी।



की प्राथमिक भूमिका पुलिस कारवाई में राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सहायता, कानून-व्यवस्था और आतंकवाद विरोध में निहित है। अंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत संघ का प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है। यह सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल (अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के रूप में जानते हैं) में से एक है जिसे 1939 में क्राउन रिप्रजेंटेटिव पुलिस के रूप में गठित किया गया था। क्राउन रिप्रजेंटेटिव पुलिस द्वारा भारत की तत्कालीन रियासतों में

मना कर दिया था, को अनुशासित करने में इस बल ने केंद्र सरकार की मदद की।

1962 के चीनी आक्रमण के दौरान एक बार फिर बल ने

घुसपैठ और सीमा पार अपराधों की जांच के लिए केरिपु बल की टुकड़ियों को भेजा गया। तत्पश्चात पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा शुरू किए गए हमलों के बाद इनको जम्मू-कश्मीर की पाकिस्तानी सीमा पर तैनात किया गया। भारत के हॉट स्प्रिंग (लद्दाख) पर पहली बार 21 अक्टूबर, 1959 को चीनी हमले को केरिपु बल ने नाकाम किया। केरिपु बल के एक छोटे से गश्ती दल पर चीन द्वारा घात लगाकर हमला किया जिसमें बल के दस जवानों ने देश के लिए एसर्वॉच्च बलिदान दिया। उनकी शहादत की अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना को सहायता प्रदान की। इस आक्रमण के दौरान केरिपु बल के 8 जवान शहीद हुए। पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर 1965 और 1971 में भारत-पाक युद्ध में भी बल ने भारतीय सेना के साथ कांधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। भारत में अर्द्ध सैनिक बलों के इतिहास में पहली बार महिलाओं की एक टुकड़ी सहित केरिपु बल की 13 कंपनियों को आतंवादियों से लड़ने के लिए भारतीय शांति सेना के साथ श्रीलंका में भेजा गया। ०००